Minister to consider the circular railway project in Calcutta. We have a suspicion that this will never be completed. If the roads are kept dug up, the whole of Calcutta will be finished. In view of this, kindly let us know about your proposal and how far you are proceeding in this matter.

SHRI MALLIKARJUN : This question does not arise on this question.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, the Cabinet Minister wanted to reply.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDAY) : There is no proposal at present for having a circular railway in Calcutta. The only proposal is that we should have a Metro railway, underground railway and that is going on and nearly Rs. 100 crores have been spent till now. I assure Hon. Members of this House that it is very sound and it will be completed as scheduled and we shall do our level best to see that the funds are not lacking.

डीजल इंजिन वर्कशाप

*265. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा डीजल इंजन वर्कशाप स्थापित किया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार उसके लिए 550 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रही है ;

(ग) क्या उस भूमि के लिए दिये जा रहे मुआवजे की दर बहुत कम है ; और

(घ) क्या भूमि की कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मुआवजे की दर बढ़ाने का है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (d). A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) There is, at present, no proposal to set up a Diesel Engine Workshop by the Railways. However, there is a scheme to set up "Diesel Component Works" at Patiala (Punjab) by the Railways for undertaking manufacture of diesel locomotive components, re-manufacture of major assemblies/sub-assemblies and re-building of diesel locomotives.

(b) It has been estimated that 550 acres of land will be required for setting up the workshops and colony. This land is being given free of cost to the Railways by the Government of Punjab.

(c) and (d). The land is being acquired by the Government of Punjab and rate of compensation is also being fixed by the State Government under the Land Acquisition Act procedure. This matter is not within the purview of the Railways.

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे सख्त एतराज है कि मैं हिन्दी में सवाल करता हूँ, मगर उसका जवाब अंग्रेजी में दिया जाता है । वे राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं ? अगर वे न जानते हों, तो मुझे कोई एतराज न हो । लेकिन श्री केदार पाण्डे बैठे हुए हैं, उनको कहना चाहिए था । इस तरीके से वे हिन्दी का, और गांधी का भी अपमान कर रहे हैं । यह गलत है । आप मंत्री जी को कहें कि वह हिन्दी में जवाब दें ।

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : अब तक यह सिस्टम रहा है कि अगर हिन्दी में सवाल है, तो हिन्दी में जवाब है और अगर अंग्रेजी में सवाल है, तो अंग्रेजी में जवाब है। अगर आप कहें कि हम केवल हिन्दी में जवाब दें और आप अंग्रेजी में बोलें.....

अध्यक्ष महोदय : इनका स्पेशल ध्यान रखा करें। जब वह हमेशा ऐसी बात कहते हैं, तो आप क्यों नहीं करते ?

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने हिन्दी में सवाल किया था, उसका जवाब हिन्दी में दें।

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर सदन के पटल पर जवाब रख दिया गया है।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह जो लिखित जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें उन्होंने यह लिखा है कि जो जमीन है वह पंजाब सरकार देगी और पंजाब सरकार का उस से सम्बन्ध है। इसका मतलब यह नहीं है कि पंजाब सरकार जमीन जो दे रही है उसकी कीमत का आपको पता नहीं है या डाका डाल कर या लूट कर भी कोई दे दे तो आप उसको ले लेंगे ? मेरा सवाल है कि वह जमीन किस भाव में ली ? पुराने वक्त में किसान से बहुत सस्ते दाम पर सरकार ने जमीन ली है। आज जमीन का भाव क्या है क्या माननीय मंत्री जी इन तमाम आंकड़ों को बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन ली वह किस भाव पर पंजाब सरकार ने ली और आज के भाव में जब कब्जा ले रही है, क्या उन किसानों को उस जमीन की पूरी कीमत दिलाने का केन्द्रीय सरकार का दायित्व है या केन्द्रीय सरकार उनको किसानों को लूटने की खुली छूट देगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : पंजाब सरकार ने यह वादा किया था कि जो जमीन चाहिए वह दी जायगी और रेलवे की तरफ से डीजल कम्पोनेंट्स वर्कशाप का निर्माण वहां किया जायेगा। हम यह नहीं जानते कि कितना पंजाब सरकार ने किसानों को दिया कितना नहीं दिया। मुआवजा और बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार के पास वह बोल सकते हैं या कोर्टस में भी जा सकते हैं। हमारा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा तो केवल वर्कशाप के निर्माण से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि मुआवजा ठीक मिले ?

श्री मल्लिकार्जुन : जी हां, हम तो चाहते हैं कि किसान को ज्यादा मुआवजा मिले।

श्री मनीराम बागड़ी : माननीय उपमंत्री महोदय जवाब दे नहीं सकते थे। केदार पाण्डे जी बैठे है उनको खुल कर जवाब देना चाहिए था। आप इस तरीके से इस को टालिए मत। हिन्दुस्तान के किसानों की जमीन जो सरकार लेती है वह कौड़ियों के दाम में लेती है। आज उस जमीन का दाम हजार रुपये गज तक है और यह दायित्व है, एक जिम्मेदारी है केन्द्रीय शासन की, अगर कोई प्रान्त या म्युनिसिपैलिटी या कोई भी संस्था जमीन को लूट कर के आपको दे दे तो आप यह कहेंगे कि वह तो लूट कर लाए थे म्युनिसिपेलिटी वाले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं ? यह बात नहीं है। आपकी पूरी तरह से यह जिम्मेदारी है, जमीन ली पंजाब सरकार ने, पंजाब सरकार की थी या पंजाब सरकार ने ली तो कितने में और क्या कीमत उसकी दी है ? क्या केन्द्रीय सरकार उन्हें पूरा मुआवजा दिलाने के बारे में अपनी जिम्मेदारी महसूस करती है ?

श्री केदार पाण्डे : जब यह स्कीम चालू हुई तो उसके मुताबिक पंजाब सरकार ने

आश्वासन दिया कि जमीन हम मुफ्त देंगे। मुफ्त में देने के माने कि उनको वह जमीन एक्वायर करनी है, जिनकी जमीन है उनसे लेनी है। तो यह पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन तो भी अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि जमीन का दाम कम मिल रहा है किसानों को तो मैं इसके बारे में पंजाब सरकार से पूछूंगा और उनसे यह भी कहूँगा कि इस पर वह विचार करें। उनको मैं पत्र लिखूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : बहुत अच्छी किसानों की हमदर्दी की आपने बात कही।

श्री केदार पान्डे : किसानों के हमदर्द हम सभी हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : अच्छी बात है मैं इसके लिए आपकी तारीफ करता हूं कि चाहे वह मौखिक ही हो लेकिन किसानों की हमदर्दी है।

मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार जो टैक्निकल मजदूर हैं उनको छोड़ कर जो और दूसरे मजदूर हैं, यह जो आपका यूनिट बन रहा है उसमें नान-टैक्निकल मजदूरों को रखने के बारे में इस बात का ध्यान रखेगी कि जिन किसानों से सरकार ने जमीन ली है, वहां पर काम जो मिल रहा है और जो काम धन्धा लग रहा है सब से पहले उस में उन लोगों को काम दिया जाएगा जिनकी जमीन सरकार ने एक्वायर की है?

श्री केदार पांडे : इस तरह की नीति ऐसे तो नहीं है लेकिन अमूमन हम लोग देखते हैं कि जिन की जमीन ली जाय उनका कोई व्यक्ति ऐसी सर्विस करने लायक हो तो उस को प्रेफरेंस दिया जाय। इस तरह की नीति हमारी हैं और ऐसा और जगह भी जहां जहां कारखाने बनते हैं वहां करते हैं, यह नीति उसमें अपनाते हैं।

SHRI XAVIER ARAKAL : Sir, it is good that diesel workshops are being put up in Punjab, But, I would like to know how many diesel workshops are to be put up. There was a proposal which is still under consideration for putting up a coach factory at Palghat in Kerala state...

MR. SPEAKER : This does not fall under this.

SHRI XAVIER ARAKAL : This is relating to putting up workshops.

MR. SPEAKER : Irrelevant question. This concerns Punjab and nothing else. You put a separate question.

SHRI XAVIER ARAKAL : This is related to the workshops—it may be in Punjab or anywhere else.

MR. SPEAKER : This is a specific question relating to Punjab. So, you put a separate question.

SHRI XAVIER ARAKAL : This is a very relevant question concerning railway workshop.

MR. SPEAKER : I am not going to allow this. This is an irrelevant question. This does not concern this question. The Minister will not have the answer for this.

Shri Rajnath Sonkar Shastri.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1956 में वाराणसी डीजल रेल इंजन कारखाना बना और उसके लिए 8 हजार से अधिक ...

अध्यक्ष महोदय : यह इर्रेलिवेन्ट है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अभी बागड़ी जी को मन्त्री जी ने बताया है कि जिन किसानों की जमीन ली गई है उन किसानों को .....

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई नया सवाल हो तो कीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा सवाल जमीन से ही संबंधित है। मैं पूछना चाहता हूं कि दो हजार व्यक्ति भूखे मर रहे हैं, उनको काम नहीं मिला है

MR. SPEAKER : This is also not relevant. Not allowed. He will not have the answer.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह इरेलिवेन्ट है।

Transport Arrangements for Asian Games

*269. SHRI AMAR ROY-PRADHAN : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Union Government has entrusted the transport arrangements for the Asian Games to the Maharashtra State Corporation; and

(b) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) and (b). No, Sir. The Maharashtra State Road Transport Corporation's role is limited only for their offer of hiring to the Asian Games authorities 200 deluxe buses to meet the transport requirements of the participants in the various events of the Games, during November, 1982.

The salient features of the offer are that the Maharashtra State Road Transport Corporation will acquire new chassis, fabricate bodies theron in its own workshop in accordance with the specifications to be indicated by the Special Organising Committee and operate these buses from the Asian Games village to various Stadia for transporting participants. After the termination of the Games the buses will be dehired. The hire charges will be based on the operational and other overhead costs.

SHRI AMAR ROY PRADHAN : I have not asked for the entire transport arrangement for the ASIAD. I have asked for a specific question. The Minister should say 'yes' or 'no'.

Is it a fact that there is some truth that 200 buses are being acquired on hire basis ? If so, I would like to know from the Hon. Minister whether regarding the hiring of buses, consultations have been done with any other State or any other State Road Transport Corporation ? I do not like you to say about the West Bengal or Kerala Government.

Have you any consultations with the Road Transport Corporations of Orissa, Bihar or any other State ? Is it a fact that Rs 15 crores have also been sanctioned to Maharashtra State Road Transport Corporation and whether any tenders had been called for this ?

SHRI VEERENDRA PATIL : Sir, there is a Transport Sub-Committee. That Transport Sub-Committee asked all the Road Transport Corporation of different States and I may inform the Hon. Member that no Road Transport Corporation except the Maharashtra Road Transport Corporation was in position to supply 200 luxury buses.